SPEED UP PARAMETERS FOR INDIAN ECONOMY

DR VARINDER BHATIA
PRINCIPAL
SLBAWA DAV COLLEGE BATALA PUNJAB

Abstract

In spite of counter effects of GST and demonetization Indian Economy is hopeful in long term perspective. India needs heavy investment in social capital. This conceptual research paper analyses speed up parameters needed for Indian economy. It puts emphasis upon the benefits of thrusts desired for health and education sectors in India.

अर्थ विवसथा से जुडी तरों ताज़ा ख़बरों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ वर्षों में विश्व के शीर्ष तीन देशों की सूची में शामिल होने वाला है अमेरिकी बैंक मेरिल लिन्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2028 तक भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. यह दावा भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को देखकर अनुमान किया गया है. इस समय ब्राजील और रूस को पीछे छोड़ भारत ब्रिक देशों में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2019 तक भारत फ्रांस और ब्रिटेन को पछाड़ देगा. इसके साथ ही यह देश जर्मनी के बाद दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है.

अमेरिकी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2028 तक भारत जर्मनी और जापान को जीडीपी (डॉलर के टर्म में) के मामले में पीछे छोड़ देगा. हालांकि इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि 2028 में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की साइज क्या होगी. रिपोर्ट में बताया गया है कि निर्भरता अनुपात में गिरावट, फाइनेंसियल मैच्युरिटी और लोगों की बढ़ती आय को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। 2028 में भारत का निर्भरता अनुपात का प्रतिशत 46.2 फीसदी रह जाएगा जबकि अभी ये अनुपात 52.2 फीसदी है। इस वजह से जीडीपी की बजत दर 32 फीसदी तक रह सकती है। इसकी तुलना 2000-17 से की जाए तो ये 31.4 फीसदी रही है। इसी के आधार पर रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारत 7.1 फीसदी की विकास दर से आगे निकलकर 10 फीसदी की विकास दर से आगे बढ़ेगा।

इसके लिए यह आवश्यक होगा कि भारत सुधारों की दिशा सामाजिक क्षेत्र की तरफ बनाए रखे। देश में सामाजिक पूंजी का सर्वथा अभाव है। भारत को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खर्च करने की आवश्यकता है। यह देश के आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी बेहद जरूरी है।

सुधार के बावजूद भारत को कारोबार सुगम बनाने (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के क्षेत्र में अभी काफी कुछ करने की आवश्यकता है। 2028 तक भारत की अर्थव्यस्था का आकार सात लाख करोड़ डॉलर (सात ट्रिलियन डॉलर) का हो जाएगा। भारतीय मुद्रा में देखें तो यह रकम 448 लाख करोड़ रुपये बैठती है। जबकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था छह लाख करोड़ डॉलर से कुछ कम और जापान की पांच लाख करोड़ डॉलर रहने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2.3 लाख करोड़ डॉलर की थी। इसलिए अभी इसका दुनिया में पांचवा स्थान है। जीएसटी के चलते बीते वित्त वर्ष की 7.1 फीसद आर्थिक विकास दर के मुकाबले चालू वर्ष में इसके धीमे रहने की संभावना है। लेकिन अगले वर्ष से इसमें सुधार दिखना शुरू हो जाएगा।

कभी-कभार उठाए जाने वाले आर्थिक सुधार के कदम नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए भारत को गतिमान आर्थिक सुधारों की जरूरत है। इसके लिए माहौल और तंत्र विकसित करना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में रोजगार की कमी को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। देश के औद्योगिक विकास रफ्तार पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम रह गई है। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में इस क्षेत्र के विकास की दर महज 3.8 फीसदी रही है, जो कि अगस्त के 4.3 फीसदी के मुकाबले आधा फीसदी कम है। लेकिन साल दर साल आधार पर अप्रैल-सितंबर छमाही में ये पिछले साल के 5.8 फीसदी से घटकर महज 2.5 फीसदी रह गई है। इसके बावजूद ई-कॉमर्स सेक्टर अगले एक दशक में 1.2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथ ही सामाजिक क्षेत्र रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा में काफी काम होना अभी बाकी है। सेवा आधारित अर्थव्यवस्था आगे भी बनी रहेगी। लेकिन सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए यह जरूरी है कि सरकार मैन्यूफैक्चरिंग, कृषि और सेवा क्षेत्र के योगदान के मौजूदा स्तर को बनाए रखे।

अर्थव्यवस्था अपने निचले स्तर से बाहर आ चुकी है और यह आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास से जुड़े तमाम विरोधाभास झूठे साबित कर सकती है यह एक सकारात्मक संकेत है फिर भी अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सरकार के अब से आगे उठाए जाने वाले परिपक्व नीतिगत क़दमों पर निर्भर करेगी. लंबे समय के लिए भारत का विकास उतार चढ़ाव और गैर बराबरी भरा रहा है। देश को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए भी अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। विशेषरूप से निजी क्षेत्र के अर्थ विवसथा में निवेश पर सभी की निगाह होगी क्योंकि इसके बिना हम महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य को नहीं पा सकते .

References

1. **"Ranking of economies - Doing Business - World Bank Group". www.DoingBusiness.org. Retrieved 2 November 2017.**
2. **"India - WTO Statistics Database". World Trade Organization. Retrieved 1 March 2017.**
3. **"Country Fact Sheets 2016". unctad.org. Retrieved 5 July 2017.**
4. **Nayak, Gayatri (15 June 2017). "CAD soars to $3.4 b or 0.6% as imports jump in Q4". The Economic Times. Retrieved 19 November 2017.**
5. **Mishra, Asit Ranjan (15 June 2017). "India current account deficit rises year-on-year as imports jump in Q4". Mint. Retrieved 19 November 2017.**
6. **"India's External Debt as at the end of March 2017" (PDF). RBI. Retrieved 5 July 2016.**
7. **"India's External Debt". Ministry of Finance, Government of India. September 2016. Retrieved 3 November 2016.**
8. **"International Investment Position". Reserve Bank of India. 29 December 2017. Retrieved 6 February 2018.**
9. **"World Economic Outlook Database, April 2017 - Report for Selected Countries and Subjects - General government gross debt". International Monetary Fund. Retrieved 4 July 2017.**